

प्रेषक,

उमेश नारायण पाण्डेय,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रबन्ध निदेशक,
सार्वजनिक उपक्रम/निगम,
उत्तराखण्ड।

औद्योगिक विकास अनुभाग- 2

देहरादून : दिनांक : 07 जनवरी, 2020

विषय:- वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत मंहगाई भत्ते के शासनादेश के अनुरूप राज्य में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी निकायों में कार्यरत ऐसे कर्मिकों, जिन्हें छठे केन्द्रीय वेतनमान के अनुसार वेतन अनुमन्य है हेतु मंहगाई भत्ता पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7, उत्तराखण्ड शासन के संलग्न शासनादेश संख्या 381/XXVII(7)02/2016, दिनांक 05 नवम्बर, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा छठे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे राज्य सरकार और स्वायत्तशासी निकायों/उपक्रमों के कर्मिकों हेतु मंहगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.07.2019 से 154% से बढ़कर 164% प्रतिमाह अनुमन्य करते हुए सार्वजनिक उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन से निकाय/उपक्रम में कार्यरत कर्मिकों को भी उक्तानुसार मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के लिए उनकी वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्तानुसार दरों पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में यथाप्रक्रिया स्वयं निर्णय लिये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।

2- अतः वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत उपरोक्त शासनादेश की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने अधीनस्थ स्वायत्तशासी संस्था/निगम/सार्वजनिक उपक्रम की वित्तीय स्थिति का आंकलन करते हुये अपने अधीनस्थ कार्यरत कर्मिकों को मंहगाई भत्ते की स्वीकृति निर्गत/अनुमन्य कराये जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सम्पन्न करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय,

(उमेश नारायण पाण्डेय)

अपर सचिव।

संख्या: 774- (1)/VII-A-2 / 2020-233(उद्योग) / 2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 05.11.2019 के क्रम में।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. अधिशासी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना एवं विज्ञान केन्द्र (NIC), सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह पतियाल)

उप सचिव।